The restructuring agenda of the Programme involve critical interventions including school mergers, remediation programme, training, monitoring teacher recruitment/ rationalization, institutional reorganisation at district and State levels and proper utilization of MIS in execution mode. Regarding this, I would like to ask the MHRD, on what basis these initiatives have been undertaken and the reasons to substantiate such radical measures to close State-aided schools. Approaching 10 years of RTE by next March, 2020, instead of strengthening the Act and moving towards complete implementation on the Act, as per RTE Forum's calculation and from media reports of the data on school closure, it is found that more than a lakh schools have been closed. I would like to know how many schools have been closed which were funded by public finance, from 2009 onwards.

श्री राजमणि पटेल : महोदय, मैं स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

SHRI JOSE K. MANI (Kerala): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

Need for steps to make barren land fertile

श्री रवि प्रकाश वर्मा (उत्तर प्रदेश): महोदय, जलवायु परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण दुष्प्रभाव जमीन के बंजरीकरण के रूप में सामने आ रहा है। बेमौसम बारिश, लगातार सूखा एवं रसायनों की अधिकता से जमीन में बढ़ता खारापन तथा धूल भरी आँधियों के कारण जमीन बंजर होने लगी है। भारतवर्ष में 32.8 करोड़ हेक्टेयर जमीन कृषि योग्य है तथा इसमें बंजर भूमि 9.6 करोड़ हेक्टेयर है, जो कि कृषि उत्पादन के लायक नही है। इसका बुरा असर खाद्यान्न के उत्पादन पर पड़ सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि अगले 10 वर्षो में तेजी से बढ़ते जा रहे बंजरीकरण के कारण लगभग 2 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन घट सकता है तथा खाद्यान्नों की कीमतें अतिरिक्त 30 प्रतिशत बढ़ सकती हैं।

आज की तारीख में खाद्यान्न की उपलब्धता घट रही है। "ग्लोबल हंगर इंडेक्स" में भारत की रैंकिंग 119 देशों में 103वें स्थान पर पहुँच चुकी है। स्टेट ऑफ इंडियाज़ एन्वॉयरनमेंट रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 30 प्रतिशत जमीन बंजर हो चुकी है। यह वैश्विक औसत से ज्यादा है। शहरीकरण तथा अन्य विकास योजनाओं के कारण भी लगभग एक प्रतिशत भूमि पर कृषि संभव नही है, परन्तु 29 प्रतिशत जमीन जलवायु बदलने की वजह से बंजर हो रही है। इन जमीनों को कृषि योग्य बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

Demand for nutritious and affordable diet for children

SHRI AHAMED HASSAN (West Bengal): Sir, recent studies have estimated that per capita cost of a daily diet, that is both nutritious and affordable, amounts to

[Shri Ahamed Hassan]

₹200/- per day. Given the *per capita* income of India, there is a real challenge in ensuring that citizens, especially children, are consuming food with the right nutritional values.

More than half the number of deaths of children under five years of age occur due to malnutrition (over 7 lakh deaths in 2017), which also poses serious maternal health issues leading to neonatal disorders in the children. Although India's under-five mortality rate has improved over the last few years, the proportion of deaths due to malnutrition has not decreased significantly.

Recent reports from various parts of the country claiming that children at schools are not being served nutritious food as part of their mid-day meal further exacerbates this problem. Taking due cognisance of this problem, the West Bengal Education Department has fixed the menu for mid-day meals at schools across the State with a nutritious combination of vegetarian and non-vegetarian food with regular servings of lentils. It is urgent that the Government aids the States in their effort to ensure that every child has access to a nutritious and affordable diet that can pave the way to a brighter future for our country.

श्री सभापति: डा. सत्यनारायण जटिया जी, आप संस्कृत में बोलेंगे या हिन्दी में बोलेंगे?

Demand to celebrate Shri Dattopanth Thengadis Birth Centenary

डा. सत्यनारायण जटिया (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं संस्कृत में बोलूंगा।

*"मुझे मेरे देश को स्वतंत्र करना है।
मैं आंदोलन करूंगा, भूखा रहूँगा।
किंतु आंदोलन नही छोड़ूंगा।"

ये उद्‌गार हैं उस बालक के जिसका नाम दत्तोपंत था। उस समय देश भर में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। इसी बालक ने आगे चलकर सन् 1955 में आज के श्रम संगठनों में देश में प्रथम स्थान पर विद्यमान भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की। "श्रमम् विना न किमपि साध्यम्?" उन्होंने श्रमिकों में राष्ट्रभाव का जागरण किया। वे राष्ट्र का औद्योगीकरण, उद्योगों का श्रमिकीकरण करना चाहते थे। वर्ष 2019 ऐसे ही राष्ट्रपुरुष का शताब्दी वर्ष है। इनका जन्म महाराष्ट्र प्रांत के वर्धा जिले के आर्वी ग्राम में 10 नवंबर, 1920 को हुआ। उन्होंने नागपुर के मोरिस कॉलेज से स्नातक तथा एल.एल.बी. विधि स्नातक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। मानव से महामानव

†Hindi translation of the original speech made in Sanskrit.